गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 109
दि. 19.08.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आज रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात हुई।

राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले सप्ताह अलास्का में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हुई अपनी बैठक के बारे में अपना आकलन साझा किया।

राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद करते हुए, प्रधानमंत्री ने कूटनीति और संवाद के जरिए संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति भारत के दृढ़ रुख को रेखांकित किया। उन्होंने दोहराया कि भारत इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है।

ट्रंप के टैरिफ अटैक के बीच पीएम मोदी ने बुलाई अहम मीटिंग, ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला

(जीएनएस)।

भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 6:30 बजे एक अहम बैठक बुलाई है. यह बैठक उनके 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर होगी, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत सात केंद्रीय मंत्री शामिल हो सकते हैं.

सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ के असर का आकलन करेंगे. हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले सभी सामान पर 25 फीसदी आयात शुल्क लगाया है.

भारतीय निर्यात पर लगेगा झटका

इतना ही नहीं, रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका ने 27 अगस्त से इस टैरिफ को दोगुना करके 50 प्रतिशत तक करने की योजना भी बनाई है. माना जा रहा है कि इस फैसले से भारतीय निर्यात को तगड़ा झटका लगेगा. खासतौर पर गहने, कपड़े और जूतों जैसे सेक्टर्स पर इसका सीधा असर पड़ सकता है. अनुमान है कि करीब 40 अरब डॉलर का भारतीय निर्यात इस कदम से प्रभावित होगा.

क्यों अहम ये बैठक?

यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे दबाव से जूझ सकता है. दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह घटनाक्रम खासा अहम माना जा रहा है. बैठक की टाइमिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज से भारत के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं.

अमेरिका का काट खोज रहा है भारत

साथ ही, विदेश मंत्री एस. जयशंकर कुछ दिनों में रूस की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं. ऐसे में भारत एक ओर जहां अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव से निपटने की रणनीति बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजिंग और मास्को के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश भी कर रहा है.

एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर अमेरिका टैरिफ को 50 प्रतिशत तक बढ़ा देता है तो भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा. कुल मिलाकर, पीएम मोदी की यह हाई-लेवल मीटिंग भारत की आर्थिक और रणनीतिक दिशा तय करने में बेहद अहम मानी जा रही है.

'चुनाव आयोग का सबसे बड़ा दुश्मन खुद आयोग का मुखिया', इण्डिया ब्लाक ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए गंभीर आरोप

(जीएनएस)।

चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इण्डिया ब्लॉक ने मोर्चा खोल दिया है। वोट चोरी और बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने संसद से लेकर सड़क तक चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

सोमवार, 18 अगस्त को दिल्ली के संविधान क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस (TMC) और वामदलों के नेताओं ने मिलकर चुनाव आयोग पर "पक्षपात और लापरवाही" के आरोप लगाए।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, डीएमके के तिरुचि शिवा और वाम दलों के सांसदों ने एक स्वर में कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था नहीं रह गया है।

विपक्ष का दावा है कि आयोग ने विपक्ष की शिकायतों पर ध्यान देने के बजाय भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां अपनाई हैं।सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने आरोप लगाया, "लगता है कि सीईसी ने विपक्षी दलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। चुनाव आयोग अब सरकार की बी-टीम बन चुका है।"

इससे पहले 17 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त ग्यानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष गलत सूचना और झूठ फैला रहा है। ज्ञानेश कुमार ने कहा, "जब राजनीति मतदाताओं को निशाना बनाकर चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर की जा रही है, तो आज आयोग साफ कर देना चाहता है कि वह निडर होकर हर वर्ग और हर धर्म के मतदाताओं के साथ खड़ा है।"

इस मामले पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार सरकार और आयोग पर हमलावर हैं। विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। राहुल गांधी ने 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू की है, जिसमें वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि वोट चोरी के खिलाफ खड़े हों।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का शहरी विकास वर्ष-2025 में महत्वपूर्ण निर्णय

कर गुजरने वाली सड़क एवं भवन विभाग की 91 सड़कों का विकास पथ योजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण करने के लिए 822 करोड़ रुपए मंजूर किए

गांधीनगर, 18 अगस्त : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के शहरों को जोड़ने और शहरों से होकर गुजरने वाली सड़कों को विकास पथ के अंतर्गत आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए 822 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय किया है।

शहरों के सर्वग्राही विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरणा से राज्य सरकार द्वारा मनाए जा रहे शहरी विकास वर्ष-2025 के अंतर्गत विकास पथ योजना के तहत ऐसी 233 किलोमीटर लंबाई की 91 सड़क एवं भवन विभाग की ऐसी सड़कों का समावेश किया गया है, जो राज्य में शहरों को जोड़ती या शहरों से होकर गुजरती हैं। तदनुसार, शहरी विकास वर्ष के तहत विकास पथ सड़कों को आवश्यकतानुसार कार्य कर अत्याधुनिक बनाया जाएगा।

विकास पथ योजना के अंतर्गत योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली ऐसी सड़क का आवश्यकतानुसार चौड़ीकरण, इलेक्ट्रिक पोल, अत्याधुनिक सड़क फर्नीचर, फुटपाथ, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, स्ट्रीट लाइट, सीसी रोड, रेलिंग जंक्शन डेवलपमेंट, बस-बे, मीडियन ब्यूटीफिकेशन और सड़क सुरक्षा के साथ-साथ मजबूतीकरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत की गई 822 करोड़ रुपए की इस बड़ी धनराशि से विकास पथ के अंतर्गत शहर की सड़कें सुदृढ़, सुंदर, मजबूत और सुविधा युक्त बनेंगी, जिससे अनेक प्रकार के लाभ होंगे और शहरी जीवन की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इतना ही नहीं, यातायात में सुरक्षा बढ़ेगी, यातायात जाम की समस्या कम होगी और यात्रा का समय कम होने से ईंधन की भी बचत होगी। आवाज और हवा का प्रदूषण कम होने से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव होगा। स्वच्छ एवं व्यवस्थित सड़कों से सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी और अधिक प्रभावी बनेंगी।

बिहार : कांग्रेस ने 55-60 सीटों पर ठोका दावा, 17 विधायकों की टिकट पक्की, राहुल गांधी का सीक्रेट प्लान तैयार

(जीएनएस)।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उलटी गिनती शुरू होते ही कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। महागठबंधन में सीटों का आधिकारिक बंटवारा अभी बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने अंदरखाने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। पार्टी की योजना है कि इस बार कम सीटों पर लड़े, मगर बेहतर स्ट्राइक रेट हासिल करे।

फिलहाल बिहार विधानसभा में कांग्रेस के 19 विधायक हैं, लेकिन सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम पार्टी से अलग हो चुके हैं। ऐसे में बचे हुए 17 विधायकों का टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है। पार्टी ने आंतरिक सर्वे के बाद तय किया है कि मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका मिलेगा। यानी इन 17 विधायकों की टिकट इस बार पक्की है।

कौन हैं वो 17 विधायक, जिन्हें कांग्रेस फिर से देगी टिकट?

इन 17 विधायकों में भागलपुर से अजीत शर्मा, किशनगंज से इजहारुल हुसैन, राजापाकर से प्रतिमा दास, सिवान से जयशंकर दुबे, औरंगाबाद से आनंद शंकर, बक्सर से मुन्ना तिवारी, करगहर से संतोष मिश्रा, जमालपुर से अजय कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर से वीरेन्द्र चौधरी, कुढ़नी से राजेश कुमार, हिसुआ से नीतू कुमारी, कटरा से अफाक आलम, राजपुर से विश्वनाथ राम, मनिहारी से मन्टोहर प्रसाद सिंह, कदवा से डॉ. शकील अहमद खान और अररिया से अब्दुर रहमान शामिल हैं।

55-60 सीटों पर फोकस, लेकिन 'स्ट्राइक रेट' पर जोर

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस बार पार्टी को महागठबंधन में 55-60 सीटें मिलने का अनुमान है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थीं, जिनमें से 19 पर जीत दर्ज की थी। अबकी बार पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि ज्यादा सीटें नहीं, बल्कि जीतने योग्य सीटें चाहिए।

पार्टी ने अब तक 45 से ज्यादा ऐसी सीटों की लिस्ट बनाई है, जहां उसका संगठन मजबूत है। इनमे पिछली बार जीती गई सभी सीटें और कुछ नई सीटें शामिल हैं।

कांग्रेस ने बिहार की कई सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। कांग्रेस ने बिस्फी, मांझी, चैनपुर, गया टाउन, टिकारी, वजीरगंज, रोसड़ा, वैशाली, लालगंज, मोहनिया, तरारी, भोरे, हाजीपुर, कुम्हरार, हलसी, मोरहर, कुशेश्वरस्थान, गोविंदपुर, बेनिपट्टी, विक्रम, नरकटियागंज, राजनगर, बख्तियारपुर, रामगढ़ और भागलपुर जैसी सीटों पर मजबूत दावा ठोका है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार थिरु सीपी राधाकृष्णन जी ने पीएम से मुलाकात की

उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार थिरु सीपी राधाकृष्णन जी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।

एक्स पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने लिखाः

"थिरु सीपी राधाकृष्णन जी से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार बनने पर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी लंबी जनसेवा और अनुभव हमारे राष्ट्र को समृद्ध करेगा। ईश्वर करे कि वे उसी समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहें जो उन्होंने हमेशा दिखाया है।"

उद्यम सखी पोर्टल महिला उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है।

उद्यम सखी पोर्टल यानी महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत विभिन्न वित्तीय योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों और सहायक संस्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह पोर्टल महिला उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने, विकसित करने और आगे बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है।

यह एमएसएमई मंत्रालय की वित्तीय योजनाओं जैसे पीएमईजीपी; सीजीटीएमएसई; मुद्रा; ट्रेड्स आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करता है।

डीआरआई ने भोपाल में अवैध दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग कारखाने का भंडाफोड़ किया; 92 करोड़ रुपये कीमत की 61.2 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त; सात गिरफ्तार

(जीएनएस)।

एक महत्त्वपूर्ण खुफिया सूचना के आधार पर, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने भोपाल में एक गुप्त मेफेड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कारखाने का, एक सुनियोजित और समन्वित ऑपरेशन, जिसका कोड नाम "ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक" था, सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया। इस ऑपरेशन के दौरान सूरत और मुंबई पुलिस ने भी डीआरआई का सहयोग किया।

डीआरआई ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापे मारे और इस गिरोह के सात प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया।

16.08.2025 को, ग्राम-जगदीशपुर (इस्लामनगर), हुजूर-तहसील, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश स्थित अवैध निर्माण इकाई की तलाशी में 61.20 किलोग्राम मेफेड्रोन (तरल रूप में) बरामद और जब्त किया गया, जिसकी अवैध बाजार में कीमत ₹92 करोड़ आंकी गई। इसके

अतिरिक्त, 541.53 किलोग्राम कच्चा माल, जिसमें मेथिलीन डाइक्लोराइड, एसीटोन, मोनोमेथिलमाइन (एमएमए), हाइड्रोक्लोरिक एसिड (एचसीएल), और 2-ब्रोमो शामिल हैं, के साथ-साथ प्रसंस्करण उपकरणों का एक पूरा सेट भी जब्त किया गया।

एकांत परिसर में जानबूझकर चारों ओर से ढके हुए कारखाने पर डीआरआई अधिकारियों ने चतुराई से छापा मारा। मेफेड्रोन बनाने वाले केमिस्ट समेत दो लोग को अवैध उत्पादन प्रक्रिया में लिप्त पाया गया।

तत्परतापूर्वक की गई कार्रवाई में, ड्रग कार्टेल के एक प्रमुख शख्स को बस्ती, उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया, जिसे भिवंडी (मुंबई) से भोपाल तक कच्चे माल की आपूर्ति की देख-रेख का काम सौंपा गया था। अवैध रूप से रसायन/ कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले दो आपूर्तिकर्ताओं को भी मुंबई में गिरफ्तार किया गया, साथ ही मुंबई से भोपाल तक रसायनों/ कच्चे माल के परिवहन के लिए जिम्मेदार शख्स को भी गिरफ्तार किया गया।

शुरूआती जांच से यह भी पता चला है कि सूरत और मुंबई से हवाला के जरिए भोपाल में पैसा भेजा जा रहा था। पैसे के लेन-देन के लिए जिम्मेदार कार्टेल के एक करीबी सहयोगी को भी सूरत में गिरफ्तार किया गया।

सरकार विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए 100 दिनों के परिवर्तन एजेंडे पर काम करेगी: श्री पीयूष गोयल

दुनिया की कोई भी ताकत भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकती: श्री पीयूष गोयल भारत दुनिया के सबसे पसंदीदा उपभोक्ता बाजार और शीर्ष निवेश स्थल के रूप में उभर रहा है: श्री पीयूष गोयल

(जीएनएस)।

सरकार भारत को तेजी से विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगले 100 दिनों के परिवर्तनकारी एजेंडे पर काम कर रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने यह बात आज दूसरे लोकमत वैश्विक आर्थिक सम्मेलन में कही।

लोगों को संबोधित करते हुए, मंत्री महोदय ने जानकारी दी कि आने वाले 100 दिन में, सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से 15 अगस्त को किए गए आ'ान का पालन करेगी, जिसमें भारत को तेज गति से आगे ले जाने, 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के विजन को लागू करने, घोषित किए गए 'पंच प्रणों' का पालन करने और यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक नागरिक 2047 तक भारत को एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने का दायित्व अपने ऊपर ले। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में 140 करोड़ भारतीय एक टीम, एक परिवार के तौर पर एकजुट होकर औपनिवेशिक मानसिकता को मिटाएंगे, भारत के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपरा का सम्मान करेंगे और राष्ट्र की एकता और अखंडता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को

एक विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकती।

श्री गोयल ने भारत की आर्थिक वृद्धि में वैश्विक विश्वास का भी संदर्भ दिया और विशेषज्ञों के इस आकलन का उल्लेख किया कि भारत दुनिया के सबसे अधिक मांग वाले उपभोक्ता बाजार और एक शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में उभरने की राह पर है। उन्होंने कहा कि यह प्रगति मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से 140 करोड़ भारतीयों के योगदान का परिणाम है, जो आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत कर रहे हैं और तन्यकशीलता पैदा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत वैश्विक मंच पर आ गया है और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, यही समय है, यही समय है।

मंत्री जी ने लोकमत समूह के संस्थापक श्री जवाहरलाल दर्डा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और एक ऐसे महान व्यक्तित्व के रूप में वर्णित किया, जिन पर हर महाराष्ट्रवासी को गर्व है।

सम्पादकीय

प्रगति के पथ पर अग्रसर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को दिल्ली एनसीआर के दो प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये दो परियोजनाएं द्वारका एक्सप्रोस वे का दिल्ली खण्ड और अर्बन एक्सटेंशन रोड–घ्घ्है। इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली में भीड़ को कम करना, कनेक्टिविटी में सुधार करना, यात्रा के समय को कम करना और प्रदूषण स्तर को घटाना है। इन दोनों परियोजनाओं की लागत 11000 करोड़ रुपए है जिसमें द्वारका एक्सप्रोस वे के दिल्ली खण्ड के लिए 5,360 करोड़ और अर्बन एक्सटेंशन रोड–घ्घ्के लिए 5,580 करोड़ का खर्च आया है।

वैसे तो यातायात सुविधाओं के लिए राजपथ का निर्माण सभी सरकारों की प्रथमिकता रही है किन्तु आजकल के आर्थिक युग में राजपथों का महत्व काफी बढ़ गया है। जरूरतों के मुताबिक राजमार्गो पर ट्रकों, बसों और कारों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यदि राजमार्गो के जाल में विस्तार नहीं होगा तो भारत विश्व विकास की दौड़ से पिछड़ जाएगा।

दूरदशा राजनेता वही है जो कल की जरूरतों का एहसास करे। स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश शासन हो या उसके पहले के शासक। किसी भी उद्देश्य के लिए राजमार्गो की जरूरतों को महसूस करके उन्होंने सड़वें बनवाईं थीं। स्वतंत्रता के बाद की सरकारों ने भी कनेक्टिविटी के विस्तार का काम किया। पंचवषाय योजनाओं में बजट निर्धारण करके राजमार्गो के निर्माण हेतु न सिर्प केन्द्र सरकार बल्कि राज्य सरकारें भी ढांचागत विकास के लिए राजमार्गो के निर्माण के लिए हमेशा ही तत्परता दिखाई है। तुलनात्मक अध्ययन से यह जरूर स्पष्ट हो जाता है कि मौजूदा सरकार लम्बी दूरी के राजमार्गो का जाल बिछाने में ज्यादा रुचि ले रही हैं क्योंकि राजमार्ग निर्माण आज व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अनिवार्य जरूरत बन गया है। किसी भी परियोजना के मूल्यांकन के मानदंड समय, जरूरत और राजस्व सामर्थ्य पर निर्भर करता है। आजादी के तुरन्त बाद तो देश को बहुत जरूरत थी राजमार्गो की किन्तु उस वक्त देश के पास इतना धन नहीं था कि हर राज्य में लम्बी दूरी राजमार्गो का निर्माण हो सके।

दरअसल वेंद्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण होते हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी यानि सार्वजनिक कार्य विभाग से राज्य सरकारें सड़क निर्माण का कार्य कराती हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायतें गांवों में सड़क निर्माण एवं रखरखाव का काम करती हैं।

धनाभाव में वेंद्र सरकारें न तो राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण पर इतना खर्च कर पाती थी और न ही राज्य सरकारें अपने संसाधनों से सड़क निर्माण कराने में बहुत ज्यादा समर्थ थीं। आज स्थिति बिल्वुल बदल गई है। वेंद्र सरकार जिन राजमार्गो को बना रहा है वह तो वेंद्रीय भूतल परिवहन विभाग के अंतर्गत है ही राज्य सरकारें भी वेंद्र की ही मदद से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत राज्यों में सड़कों का जाल बिछा रही हैं। यही नहीं ग्राम पंचायतों को भी वेंद्र सरकार से ही धन मिल रहा है।

बहरहाल किसी भी देश का विकास जानने के लिए वहां की सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई अड्डों की गणना की जाती है। शहरों के विकास के लिए आजकल मेट्रो रेल होना आवश्यक हो गया है उसी तरह एक राज्य से दूसरे–तीसरे और चौथे के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले राजमार्गो को राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है और इस सरकार के वेंद्रीय भूतल परिवहन विभाग ने बिना किसी भेदभाव के एक साथ कई–कई राज्यों को जोड़कर सड़क परिवहन के क्षेत्र में व्रांति ला दी है।

यह एक संयोग ही है कि सभी राज्य चाहे वे किसी भी पाटा की हों, सभी वेंद्रीय परियोजनाओं के तहत राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण से खुश हैं और यथासंभव वेंद्र के साथ सहयोग भी कर रहे हैं। सबसे जीवंत उदाहरण है हिमाचल प्रदेश। इस राज्य के तमाम राजमार्ग संकरे और खतरनाक मोड़ वाले थे। वेंद्रीय भूतल परिवहन ने टनल, फ्लाईं ओवर और खतरनाक मोड़ों को चौड़ा करके इतना सुगम बना दिया है कि अब राज्य की परिवहन व्यवस्था काफी सुचारू होने लगी है।

नकली खाद–बीज की बिक्री के मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिए कार्रवाई के आदेश

नकली खाद–बीज पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग और आईसीएआर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्चस्तरीय बैठक

फसलें खराब होने को अत्यंत गंभीरता से लें अधिकारी, सैंपल फेल होने पर कार्रवाई की जाएं– श्री शिवराज सिंह

एक नहीं, सैकड़ों किसान हो रहे हैं परेशान, किसानों की पीड़ा को गंभीरता से समझें– श्री शिवराज सिंह

नकली खाद, बीज और कीटनाशक किसानों के लिए अभिशाप है– श्री शिवराज सिंह

(जीएनएस)। नकली खाद–बीज और कीटनाशकों की बिक्री के मामले में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा रूख अपनाया है। श्री शिवराज सिंह ने आज कृषि भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के वरिष्ठ अधिकारियों की इस संबंध में उच्चस्तरीय बैठक लेकर नकली खाद–बीज व कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों की फसलें खराब होने को सभी अधिकारी अत्यंत गंभीरता से अधिकारी लें, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सकें। श्री शिवराज सिंह ने व्यापक पैमाने पर छापेमारी और खेतों में जाकर जांच करने के निर्देश भी दिए हैं।

बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि नकली खाद–बीज और कीटनाशकों के कारण कोई एक नहीं, बल्कि विभिन्न जिलों में सैकड़ों किसान परेशान हो रहे हैं। कई जगह से ऐसी शिकायतें आती है, किसान बोलते हैं कि खेत में दवाई डाल रहे हैं पर इसका असर नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत चिंतित हूं। इन किसानों की पीड़ा को गंभीरता से समझा जाना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि मैंने कल खुद किसान के खेत में जाकर देखा, एक दवाई किसान ने डाली, जिसके कारण सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। कल जब मैंने खेत में देखा तो

सैकड़ों किसान वहां मौजूद थे। इन सबने मुझे शिकायतें की, परेशानी बताई। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि ऐसे घटिया या नकली दवाई और खाद–बीज बेचने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएं। केंद्रीय मंत्री ने कृषि अधिकारियों से इस संबंध में अब–तक की गई कार्रवाई की जानकारी लेते हुए कहा कि नकली खाद, बीज और कीटनाशक किसानों के लिए अभिशाप है। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि हम हमारे किसानों को लूटते हुए नहीं देख सकते।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने निर्देश दिए कि कृषि विभाग का अमला राज्य सरकारों के साथ किसानों के खेतों में जाकर जांच करें और अभियान चलाकर व्यापक पैमाने पर आकस्मिक छापेमारी कर कड़ी कार्रवाई करें। सैंपल लिए जाएं व फेल होने पर कार्रवाई करें। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि जो कंपनी या निमार्ता गड़बड़ियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे तो गड़बड़ करने वाले लोगों में भय पैदा होगा और किसानों को राहत मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि गड़बड़ी मिलने पर फैक्ट्रियां व दुकानें सील की जाएं।

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो किसानों के हित में कड़ी कार्रवाई करना हमारा धर्म है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो नहीं होने दें, यह हमारी ड्यूटी है, जिसका पालन हमें करना है। श्री शिवराज सिंह ने इस संबंध में किसानों की शिकायतों को भी सुनने के साथ उनका पूरा समाधान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि प्राप्त शिकायतों की वे स्वयं नियमित समीक्षा करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ बात करके किसानों के मामले में पूरी संवेदना के साथ प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। श्री शिवराज सिंह ने इस संबंध में किसानों के बीच जागरूकता का प्रसार भी व्यापक रूप से करने के दिशा–निर्देश दिए, ताकि किसान परेशान होने से बच सकें।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान भी किसानों के बीच प्रचार–प्रसार किया जाएं, ताकि किसान नुकसान और परेशानी से बच सकें। श्री शिवराज सिंह ने एक अन्य विषय में पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, मैकेनाइजेशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी सहायता का कृषि विभाग की टीमों के द्वारा सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह चेक किया जाना चाहिए कि पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, मैकेनाइजेशन के लिए केंद्र से दी जा रही सब्सिडी का लाभ किसानों को वास्तविक रूप से कितना मिल रहा है।

आईबीसी ने व्यापार सुगमता और परिसंपत्ति प्राप्ति को बढ़ावा दिया

आईबीसी के अंतर्गत 1,194 कंपनियों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया, इससे लेनदारों को ₹3.89 लाख करोड़ की वसूली संभव हुई

दिवालियापन ढाँचे को मजबूत करने और देरी को कम करने के लिए छह विधायी संशोधन और 100 से ज्यादा नियामक बदलाव किए गए

वित्त वर्ष 2024–25 में बैंकों की लगभग आधी वसूली आईबीसी के खाते में होगी

(जीएनएस)। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) ने भारत के दिवाला ढाँचे को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की प्रमुख उपलब्धि वित्तीय रूप से संकटग्रस्त कंपनियों का समाधान करने और लेनदारों द्वारा वसूली करने की इसकी क्षमता रही है। पुनरुद्धार के लिए एक स्पष्ट और समयबद्ध ढाँचा प्रदान करके, आईबीसी ने लेनदारों का विश्वास मजबूत किया है और घरेलू तथा विदेशी निवेश दोनों को प्रोत्साहित किया है। आईबीसी ने भारत में व्यापार करने की सुगमता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने एक तेज और अधिक संरचित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की है। इससे परिसंपत्तियों का मूल्य अधिकतम हो रहा है, उद्यमशीलता को बढ़ावा मिल रहा है, ऋण की उपलब्धता बढ़ रही है और सभी हितधारकों के हितों में संतुलन बना रहा है। 31 मार्च, 2025 तक आईबीसी ढांचे के अंतर्गत कुल 1,194 कंपनियों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है। इन मामलों के माध्यम से लेनदारों को ₹3.89 लाख करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। यह आईबीसी प्रक्रिया में प्रवेश के समय मूल्यांकन किए गए इन कंपनियों के परिशोधन

मूल्य के 170 प्रतिशत से अधिक और उचित मूल्य के 93 प्रतिशत से अधिक है।

आईबीसी ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरबीआई की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जून 2025) के अनुसार सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (जीएनपीए) में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यह मार्च 2025 के अंत तक 2.3 प्रतिशत के बहु–दशकीय निम्नतम स्तर पर पहुँच गई है। यह कमी एक मजबूत और अधिक स्थिर बैंकिंग प्रणाली का संकेत देती है। 2023–24 के लिए भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति

पर आरबीआई की (26 दिसंबर 2024 को जारी) रिपोर्ट के अनुसार है कि एससीबी ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से कुल ₹96,325 करोड़ की वसूली की। इसमें से अकेले आईबीसी चैनल ने ₹46,340 करोड़ का महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह कुल वसूलियों का 48.1 प्रतिशत है। सरकार ने आईबीसी में छह विधायी संशोधन किए हैं और इसकी स्थापना के बाद से नियमों में 100 से अधिक बदलाव किए हैं। ताकि दिवाला समाधान ढांचे को मजबूत किया जा सके और प्रक्रियात्मक दक्षता को बढ़ाया जा सके जिससे देरी को कम किया जा सके।

आईबीसी ने कंपनियों और उनके देनदारों के बीच व्यवहारिक बदलाव लाया है। चूक करने वाली कंपनियां स्वामित्व खो सकती हैं यह विश्वसनीय खतरा पैदा करके इस संहिता ने देनदारों और लेनदारों के बीच संबंधों को मौलिक रूप से बदल दिया है।

दिवाला पेशेवरों (आईपी) की क्षमता निर्माण के लिए कई पहल की गई हैं। वित्त वर्ष 2024–25 में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने व्यावहारिक कौशल बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं, वेबिनार और सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित की। इसने प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विश्व बैंक, भारतीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के संस्थान (आईआईसीए) और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) जैसे विशेषज्ञ निकायों के साथ भी सहयोग किया। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने वैश्विक विशेषज्ञों को एक साथ लाया, जिससे आईपी को सर्वोत्तम प्रथाओं का बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ।

यह जानकारी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और जमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने आज लोकसभा में दी।

₹74,052 करोड़ से अधिक लागत की 23 परियोजनाओं की समीक्षा की गई

परियोजना मॉनिटरिंग समूह (पीएमजी), डीपीआईआईटी ने महाराष्ट्र में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की अध्यक्षता की

शहरी परिवहन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएमजी ने एमयूटीपी चरण–IIIE और सिनारमास पश्चिम तट परियोजना की समीक्षा की

(जीएनएस)। महाराष्ट्र राज्य में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों की समीक्षा के लिए परियोजना मॉनिटरिंग समूह (पीएमजी) की एक उच्च–स्तरीय बैठक 14.08.2025 को आयोजित की गई।

23 महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़े कुल 28 मुद्दों की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत ₹74,052 करोड़ से अधिक है। ये परियोजनाएँ महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जिनमें रेलवे क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

समीक्षा की गई परियोजनाओं में, ₹33,690 करोड़ के निवेश वाली मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) चरण–IIIE पर विस्तार से चर्चा की गई। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य मुंबई महानगर क्षेत्र में उपनगरीय रेल क्षमता को बेहतर करना, भीड़भाड़ कम करना और यात्री सुविधाओं में सुधार करना है। इस

परियोजना में भारत की वित्तीय राजधानी में सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त रेल लाइनों का निर्माण, सिग्नलिंग प्रणालियों का आधुनिकीकरण और नए रोलिंग स्टॉक की खरीद शामिल है।

रायगढ़ जिले में ₹10,500 करोड़ के निवेश वाली एक प्रमुख औद्योगिक पहल, सिनारमास पश्चिम तट परियोजना की भी समीक्षा की गई। सिनारमास पल्प एंड पेपर की यह परियोजना भारत की लुगदी और कागज निर्माण क्षमता को बेहतर करेगी, जरूरी रोजगार पैदा करेगी और डाउनस्ट्रीम उद्योगों को आकर्षित करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढाँचे और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाएँ स्थापित करना है।

बैठक की अध्यक्षता उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के प्रधान आर्थिक सलाहकार श्री प्रवीण महतो ने की और इसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और परियोजना प्रस्तावकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में परियोजना मॉनिटरिंग समूह (पीएमजी) की ओर से सुगम अंतर–मंत्रालयी और राज्य समन्वय के माध्यम से मुद्दों के समाधान में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

डीपीआईआईटी के प्रधान आर्थिक सलाहकार ने परियोजना निगरानी के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई और संबंधित अधिकारियों को लंबित मुद्दों के समाधान में सक्रिय रुख अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने और केंद्र सरकार, राज्य प्राधिकरणों और निजी हितधारकों के बीच सहयोग के माध्यम से अपनी चिंताओं का कुशल और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए परियोजना मॉनिटरिंग समूह (पीएमजी) (https://pmg.dpiit.gov.i»»f/) की इस विशिष्ट व्यवस्था का लाभ उठाने वाले निजी सहयोगियों के महत्व पर जोर दिया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सहायक निदेशक भाविना पटेल ने अमरीका के स्पोकेन में आईटीटीएफ विश्व पैरा इवेंट्स में इतिहास रचा

भाविना ने आईटीटीएफ वर्ल्ड पैरा एलीट स्पर्धा में स्वर्ण और आईटीटीएफ वर्ल्ड पैरा फ्यूचर इवेंट में महिला एकल वर्ग 4–5 श्रेणी में रजत पदक जीता

दो पदकों की जीत ने भाविना को टेबल टेनिस की महिला एकल श्रेणी के व्हीलचेयर (क्लास 1 से 5) में आईटीटीएफ विश्व पैरा रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचा दिया

(जीएनएस)। अहमदाबाद में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के क्षेत्रीय कार्यालय में सहायक निदेशक सुश्री भाविना पटेल ने अमरीका में वाशिंगटन के स्पोकेन में आयोजित दो प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शीर्ष सम्मान हासिल करके भारत को बहुत गौरवान्वित किया है।

भाविना ने 9 से 13 अगस्त 2025 तक, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (आईटीटीएफ) विश्व पैरा एलीट स्पर्धा में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए महिला एकल वर्ग 4–5 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। यह जीत दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ियों के सामने उनके असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और रणनीतिक खेल कौशल का परिणाम है।

भाविना ने इससे कुछ ही दिन पहले, 6 से 8 अगस्त 2025 तक स्पोकेन में ही आयोजित आईटीटीएफ वर्ल्ड पैरा फ्यूचर इवेंट में के इसी वर्ग

में रजत पदक जीता था, जिससे वैश्विक मंच पर उनकी निरंतरता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता काफी बढ़ गई है।

सुश्री भाविना पटेल लगातार दो बार पोडियम पर स्थान पाने के साथ ही अब पैरा टेबल टेनिस में क्लास 1 से 5 तक की महिला श्रेणियों में महिला सिंगल्स के लिए विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं – जो भारतीय खेलों में एक ऐतिहासिक क्षण है और उत्कृष्टता के संदर्भ में उनकी अथक मेहनत का प्रमाण है।

भाविना पटेल की ये उपलब्धियां व्यक्तिगत विजय से कहीं आगे हैं और वे देश भर के एथलीटों, विशेषकर पैरा–खेल क्षेत्र के एथलीटों के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। वे इस विश्वास को मजबूत करती हैं कि समर्पण और दृढ़ता से किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपनी संगठनात्मक संस्कृति के भाग के रूप में सदैव अपने कर्मचारियों को खेल और शारीरिक फिटनेस गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया व समर्थन दिया है। निगम का मानना है कि कर्मचारियों में खेल भावना को बढ़ावा देने से न केवल उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान मिलता है, बल्कि अनुशासन, टीमवर्क तथा दृढ़ता जैसे मूल्यों का भी विकास होता है, जो कार्यस्थल पर प्रदर्शन को बेहतर करते हैं। पिछले कई वर्षों से, ईएसआईसी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने राष्ट्रीय एवंअंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और संगठन खेल उपलब्धियों के लिए संसाधनों, अवकाश तथा मान्यता के संदर्भ में आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

भाविना पटेल की ऐतिहासिक सफलता इस बात का गौरवपूर्ण उदाहरण है कि कैसे निगम का खेलों के प्रति सहयोग कर्मचारियों को अपने जुनून के साथ अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को संतुलित करने में मदद कर सकता है, जिससे वे विश्व मंच पर चमकने में सक्षम हो सकते हैं।

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में प्रस्तुत

विधेयक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सुधार एजेंडे का विस्तार करता है

16 अधिनियमों के 288 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया

76 मामलों में पहली बार उल्लंघन करने पर सलाह या चेतावनी दी जाएगी

यह विधेयक छोटे दंडों को तर्क पर आधारित बनाता है, बार–बार अपराध करने पर दंड में बढ़ोतरी करता है

(जीएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। इस विधेयक को पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर किया जा चुका है। माननीय मंत्री ने माननीय अध्यक्ष से विधेयक को सेलेक्ट कमिटी को भेजने का अनुरोध भी किया है। समिति के सदस्यों का चयन माननीय अध्यक्ष की ओर से किया जाएगा और समिति अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

यह प्रक्रिया जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 की सफलता पर आधारित है – जो विभिन्न अधिनियमों में छोटे अपराधों को व्यवस्थित रूप से अपराधमुक्त करने वाला पहला समेकित कानून है। 11 अगस्त 2023 को अधिसूचित 2023 अधिनियम ने 19 मंत्रालयों/ विभागों की ओर से प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त कर दिया।

2025 विधेयक इस सुधार एजेंडे का विस्तार करते हुए 10 मंत्रालयों/ विभागों की ओर से प्रशासित 16 केंद्रीय अधिनियमों को इसमें शामिल करता है। कुल 355 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है – 288 प्रावधानों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन देने के लिए गैर–अपराधीकरण किया जाएगा, और 67 प्रावधानों में जीवन सुगमता को सुगम बनाने के लिए संशोधन का प्रस्ताव है।

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 में जीवन सुगमता को सुगम बनाने के लिए नई दिल्ली नगर परिषद् अधिनियम, 1994 (एनडीएमसी अधिनियम) और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 67 संशोधनों का भी प्रस्ताव है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएं:

पहली बार उल्लंघनः 10 अधिनियमों के अंतर्गत 76 अपराधों के लिए सलाह या चेतावनी। गैर–अपराधीकरणः मामूली, तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक के लिए कारावास की धाराओं को मौद्रिक दंड या चेतावनी से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

दंडों का युक्तिकरणः दंड को आनुपात पर आधारित बनाया जाएगा, और बार–बार होने वाले अपराधों के लिए क्रमिक दंड दिया जाएगा।

न्यायनिर्णयन तंत्रः प्रशासनिक प्रक्रियाओं के जरिए दंड लगाने के लिए नामित अधिकारियों को सशक्त बनाया जाएगा, जिससे न्यायिक बोझ कम होगा।

जुमार्ने और दंड में संशोधनः विधायी संशोधनों के बिना निवारण बनाए रखने के लिए हर तीन साल में स्वचालित रूप से 10% की बढ़ोतरी।

चाय अधिनियम, 1953, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009, मोटर वाहन अधिनियम, 1988, और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, जैसे चार अधिनियम, जन विश्वास अधिनियम, 2023 का हिस्सा थे और वर्तमान विधेयक के अंतर्गत इनका और अधिक गैर–अपराधीकरण करने का प्रस्ताव है।

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 भारत की नियामक सुधार यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दशार्ता है और सतत आर्थिक विकास और बेहतर व्यावसायिक सुगमता को प्रोत्साहन देगा।

प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना पोर्टल लाइव

प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के लिए पंजीकरण की सुविधा हेतु पोर्टल, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की थी

लगभग ₹1 लाख करोड़ के परिव्यय वाली यह योजना, 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगी

प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देगी

(जीएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में घोषित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने वाला प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल लाइव हो गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। ₹99,446 करोड़ के परिव्यय के साथ, इस योजना का उद्देश्य दो वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 और 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा।

यह योजना नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नव–नियोजित युवाओं को दो किस्तों में ₹15,000 तक और नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी ₹3000 प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।

योजना के भाग अ के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (ABPS) का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के माध्यम से किए जाएँगे। भाग इ के अंतर्गत नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन–लिंक्ड खातों में किया जाएगा।

नियोक्ता अब प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना पोर्टल (https://pmvbry.epfi»»fdia.gov.in ¹ff https:// pmvbry.labour.gov.in) पर जाकर एकमुश्त पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

सभी पहली बार नौकरी करने वालों को उमंग ऐप पर उपलब्ध फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) के माध्यम से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जनरेट करना होगा।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

'विरासत और स्वदेशी वस्त्र' पर दो सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र कार्यक्रम का आयोजन

वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) के अंतर्गत

(जीएनएस)।

वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) के अंतर्गत "विरासत और स्वदेशी वस्त्र" पर दो सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा इस संबंध में विदेश मंत्रालय के साथ सहयोग का यह पहला अवसर है। इस कार्यक्रम में 16 देशों के 26 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और इसका आयोजन भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी), वाराणसी द्वारा 18 से 29 अगस्त, 2025 तक किया जा रहा है।

18 अगस्त, 2025 को आयोजित उद्घाटन सत्र में विकास आयुक्त (हथकरघा) डॉ. एम. बीना मुख्य अतिथि रहीं। कार्यक्रम का उद्घाटन

करते हुए उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि भारतीय वस्त्रों का अध्ययन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन है। भारत की प्रत्येक बुनाई उसकी संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है और प्रत्येक बुनाई एक दास्तान सुनाती है।

उन्होंने हथकरघा में समाहित स्थायित्व के महत्व और आईआईटी दिल्ली के कार्बन क्रेडिट अध्ययन के माध्यम से इसकी पुष्टि किए जाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने 'मूल की ओर लौटने' की आवश्यकता पर भी जोर दिया क्योंकि हथकरघा को अपनाना पीछे मुड़कर देखना नहीं, बल्कि एक हरित भविष्य की तलाश है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पाठ्यक्रम 'बनारस' और भारतीय वस्त्र परंपराओं का गहन अनुभव प्रदान करेगा।

आईटीईसी कार्यक्रम, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का अग्रणी और सबसे पुराना क्षमता निर्माण मंच है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी और जिसके तहत 160 से अधिक देशों के 2,00,000 से अधिक अधिकारियों को नागरिक और रक्षा क्षेत्र दोनों में प्रशिक्षित किया गया है।

"विरासत/स्वदेशी वस्त्र" पर आईटीईसी दो-सप्ताह का पाठ्यक्रम विभिन्न देशों के नीति निमार्ताओं, व्यवसायियों और वस्त्र पेशेवरों के लिए भारत की समृद्ध विरासत/स्वदेशी वस्त्रों का पता लगाने और वैश्विक वस्त्र बाजार में भारतीय हथकरघा क्षेत्र की अभिन्न भूमिका को समझने के लिए तैयार किया गया है। यह पाठ्यक्रम भारतीय हथकरघा परंपराओं, उनके महत्व, तकनीकों, संरक्षण और वैश्विक व्यापार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए हथकरघा समूहों और भारत के प्रमुख संस्थानों/केंद्रों के गहन क्षेत्रीय दौरों के अवसर प्रस्तुत करता है।

आईआईएचटी, वाराणसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1956 में हथकरघा क्षेत्र में आधुनिक तरीकों और नवीनतम बदलावों के बारे में तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी।

'प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए स्वदेशी एआई-संचालित रक्त परीक्षण उपकरण का समर्थन किया'

टीडीबी ने आईओटी-सक्षम एआई-संचालित पॉइंट-ऑफ-केयर रक्त परीक्षण उपकरण के लिए मेसर्स प्राइमरी हेल्थटेक प्राइवेट लिमिटेड को सहयोग दिया

(जीएनएस)।

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने मेसर्स प्राइमरी हेल्थटेक प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ 'एआई/एमएल एल्गोरिदम द्वारा संचालित किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा के लिए आईओटी-सक्षम पॉइंट-ऑफ-केयर रक्त परीक्षण उपकरण' नामक परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

आईआईटी गुवाहाटी के पूर्व छात्र श्री साहिल जगनानी और श्री अंकित चौधरी द्वारा स्थापित, यह कंपनी डॉक्टरों, शोधकताओं, उद्यमियों, प्रोफेसरों और छात्रों की एक बहु-विषयक टीम से उभरी है, जो वंचित आबादी के लिए किफायती नैदानिक तकनीकें विकसित करने के लिए काम कर रही है। उनके सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास, जिसे शुरू में बीआईआरएसी का सहयोग प्राप्त था, ने मोबिलैब डिवाइस का निर्माण किया—एक पोर्टेबल, बैटरी से चलने वाला क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइजर, आईओटी-सक्षम और एआई/एमएल एल्गोरिदम द्वारा संचालित, जो किडनी, लिवर, हृदय, विटामिन और कैंसर से संबंधित 25 से अधिक मापदंडों का परीक्षण करने में सक्षम है।

कंपनी के पास आईआईटी गुवाहाटी से हस्तांतरित "पॉइंट-ऑफ-केयर क्वांटिफिकेशन के लिए एक ट्रांसमिटेंस-आधारित प्रणाली/किट" का पेटेंट है और उसने एकीकृत मिक्सर, परख विकास, सेंट्रीफ्यूज और प्रोपराइटरी ऑप्टिकल सिस्टम से संबंधित छह से ज्यादा अतिरिक्त पेटेंट आवेदन दायर किए हैं। इस उपकरण का 10,000 मरीजों पर परीक्षण हो चुका है और हाल ही में इसे सीडीएससीओ से निर्माण लाइसेंस मिला है।

यह परियोजना वर्तमान प्रोटोटाइप (एम1) को उन्नत बनाने पर केंद्रित होगी ताकि एक साथ पाँच परीक्षण किए जा सकें, रोगियों के प्रतीक्षा समय को कम किया जा सके और व्यावसायिक स्तर पर विनिर्माण स्थापित किया जा सके। इस अगली पीढ़ी के मोबिलैब में हीमोग्लोबिन, क्रिएटिनिन, बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, यूरिक एसिड, ग्लूकोज और जीजीटी जैसे परीक्षण शामिल होंगे।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के सचिव, श्री राजेश कुमार पाठक ने इस अवसर पर कहाः

"ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंच सुनिश्चित करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। यह परियोजना न केवल सामर्थ्य और पहुंच को संबोधित करती है, बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए स्वदेशी, एआई-संचालित नैदानिक समाधान विकसित करने में देश की क्षमता को भी प्रदर्शित करती है।"

प्राइमरी हेल्थटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों ने आभार व्यक्त करते हुए कहाः

"प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का सहयोग प्रयोगशाला नवाचार से लेकर बड़े पैमाने पर तैनाती तक की हमारी यात्रा को गति देगा। मोबिलैब के साथ, हमारा लक्ष्य ग्रामीण और वंचित समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा की कमी को पूरा करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि देश में कहीं भी, देखभाल के बिंदु पर उन्नत निदान उपलब्ध हों।"

यह सहयोग टीडीबी की आत्मनिर्भर भारत के साथ स्वदेशी स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर सस्ती चिकित्सा प्रौद्योगिकियों में देश की उपस्थिति को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए

उद्यम और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म ने पूरे भारत में 6.63 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत किए

(जीएनएस)।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया गया है: -

कारोबार में आसानी हेतु एमएसएमई के लिए उद्यम पंजीकरण 1.7.2020 से प्रभावी।

अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औपचारिक दायरे में लाने हेतु उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (यूएपी) का शुभारंभ।

खुदरा और थोक व्यापारियों को 2.7.2021 से एमएसएमई के रूप में शामिल करना।

एमएसई के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की सुविधा प्रदान करने और रोजगार के अवसरों का विस्तार करने हेतु 9,000 करोड़ रुपये की आवश्यक धनराशि के साथ ऋण गारंटी योजना का पुनर्गठन किया गया।

18 व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण लाभ प्रदान करने के लिए 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' योजना का शुभारंभ।

आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष की स्थापना उन एमएसएमई में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपये डालने के लिए की गई है, जिनमें विकसित होकर बड़ी इकाइयाँ बनने की क्षमता और व्यवहार्यता है।

90% तक गारंटी कवरेज वाले एमएसई को विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए 10 करोड़ रुपये (01.04.2025 से प्रभावी) तक की सीमा तक संपार्श्विक मुक्त ऋण, क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

एमएसएमई को विलंबित भुगतान की समस्या का समाधान करने के लिए, कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों, जिनमें सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) शामिल हैं, से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण को सुगम बनाने के लिए व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) की स्थापना की गई है।

विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये और विनिर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिससे इस योजना का दायरा बढ़ गया है।

01.07.2020 से 31.07.2025 तक अखिल भारतीय स्तर पर उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत एमएसएमई की कुल संख्या 6.63 करोड़ है।

यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

इण्डिया गठबंधन की ओर से कौन होगा उपराष्ट्रपति उम्मीदवार? उद्धव ठाकरे गुट का आया बड़ा बयान

(जीएनएस)।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल की कुर्सी संभाल रहे सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बना कर भाजपा ने विपक्षी इंडिया गठबंधन को सरप्राइज कर दिया है। राधाकृष्णन को एनडी की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब सभी की निगाहें विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पर टिकी हुई है।

विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए कई नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना यूबीटी ने इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद के भावी उम्मीदवार के नाम को लेकर बड़ा बयान दिया है।

बता दें देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है। नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बचे हुए कार्यकाल तक रहेगा। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वहीं विपक्ष की ओर

से अभी तो उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं हुआ है लेकिन ठाकरे गुट ने बयान देकर सारी तस्वीर साफ कर दी है।

उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए किसके नाम की हो रही चर्चा?

दरअसल, इंडिया गठबंधन की ओर से डीएमके सांसद तिरुचि शिवा को विपक्ष के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वो ही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। हालांकि उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद शिवा की उम्मीदवारी का दावा खटाई में पड़ता नजर आ रहा है।

उद्धव ठाकरे गुट ने बताई सच्चाई?

शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने बताया कि विपक्ष के नेता जल्द ही बैठक कर इस मुद्दे पर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि अभी किसी नाम पर सहमति नहीं बनी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सवाल पर उन्होंने कहा कि "अभी पता नहीं है। हमारे विपक्ष के नेता इकट्ठे बैठकर चर्चा करेंगे।"

कौन हैं तिरुचि शिवा?

तिरुचि शिवा एक अनुभवी राजनेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं। वह तमिलनाडु से डीएमके पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका नाम इसलिए चर्चा में है, क्योंकि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी तमिलनाडु से हैं।

तिरुचि शिवा ने 1996 में पहली बार लोकसभा सदस्य बने थे। इसके बाद, वह जनवरी 2000, जुलाई 2007, 2014 और अप्रैल 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए।

तिरुचि एमए (अंग्रेजी) और बीएल की शिक्षा पेरियार ईवीआर कॉलेज, मद्रास विश्वविद्यालय और तिरुचि लॉ कॉलेज, भारतीदासन विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। उनकी शिक्षा और राजनीतिक अनुभव उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाते हैं।

संसदीय प्रश्नः पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नए नियम

(जीएनएस)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में दूषित स्थलों की पहचान और प्रबंधन के लिए 24.07.2025 को पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं। संदूषित स्थलों की पहचान, निर्धारण और उपचारण की प्रक्रिया को उपरोक्त नियमावली के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

इन नियमों के अंतर्गत, संदूषित स्थल को संदूषकों से प्रभावित क्षेत्र अथवा स्थल के रूप में परिभाषित किया गया है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा संदूषक को संदूषित स्थल के रूप में घोषित किया गया है, यदि संदूषक विस्तृत स्थल मूल्यांकन पूरा करने के बाद निर्धारित प्रारंभिक स्तरों से अधिक पाया जाता है।

स्थानीय निकाय या जिला प्रशासन को स्वयं या जनता से शिकायत प्राप्त होने पर, नियमों में निर्धारित जानकारी को ध्यान में रखते हुए संदूषकों से प्रभावित क्षेत्र की पहचान करने और केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपने अधिकार क्षेत्र में संदिग्ध दूषित स्थलों के रूप में ऐसे सभी क्षेत्रों की सूची बनाने का आदेश दिया गया है।

संदिग्ध संदूषित स्थलों की सूची प्राप्त होने पर एसपीसीबी/पीसीसी को स्वयं अथवा किसी संदर्भ संगठन के माध्यम से सूची प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर संदिग्ध संदूषित स्थल का नमूना लेकर और विश्लेषण करके संदिग्ध संदूषित स्थल का प्रारंभिक स्थल मूल्यांकन करने का अधिदेश दिया गया है। एसपीसीबी/पीसीसी संदिग्ध संदूषित स्थल को सूचीबद्ध कर सकती है क्योंकि संदूषक का संभावित संदूषित स्थल निर्धारित जांच स्तरों से अधिक पाया जाता है।

इसके अतिरिक्त, एसपीसीबी/पीसीसी को स्वयं अथवा किसी संदर्भ संगठन के माध्यम से संभावित संदूषित स्थल के सूचीबद्ध होने की तारीख से तीन माह के भीतर संभावित संदूषित स्थल के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करते हुए विस्तृत नमूने और विश्लेषण द्वारा संभावित संदूषित स्थल का विस्तृत स्थल मूल्यांकन करने का अधिदेश दिया गया है।

एसपीसीबी/पीसीसी विस्तृत स्थल मूल्यांकन पूरा करने के बाद स्थल को संदूषक निर्धारित अनुक्रिया का अधिदेश दिया गया है। एसपीसीबी/पीसीसी को केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर संदूषित स्थलों की सूची प्रकाशित करने का अधिदेश दिया गया है जिसमें ऐसे प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर प्रभावित होने की संभावना वाले हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त होने पर, एसपीसीबी / पीसीसी को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दूषित स्थलों की अंतिम सूची प्रकाशित करने और आम नागरिकों की जानकारी के लिए क्षेत्र में परिचालित दो स्थानीय समाचार पत्रों में इस संबंध में एक नोटिस प्रकाशित करने और इस संबंध में बरती जाने वाली सावधानी का भी उल्लेख करने का आदेश दिया गया है।

जिम्मेदार व्यक्ति को एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा निर्देश की तारीख से छह महीने के भीतर एक उपचारी योजना तैयार करने, एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा उपचारण योजना के अनुमोदन के बाद उपचारण शुरू करने और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

अनाथ संदूषित स्थलों और बैंकों के अस्थायी कब्जे वाले स्थलों अथवा न्यायिक कार्यवाहियों के मामले में एसपीसीबी/पीसीसी को उपचारण योजना तैयार करने और उपचारी कार्यकलापों का संचालन करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। इस संबंध में उपचारी कार्यकलापों के लिए व्यय का वहन केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा नियमों में निर्धारित अनुपात और तरीके से किया जाना है।

जिला या ब्लॉक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी

(जीएनएस)।

भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित संकेतकों का उपयोग करके सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जो देश की विशिष्ट प्राथमिकताओं और विकासात्मक आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। इस संबंध में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की निगरानी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य हितधारकों के परामर्श से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (एनआईएफ) विकसित किया है। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में एकीकृत करने के प्रयास के तहत सतत विकास लक्ष्यों को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ संरेखित किया है। भारत सरकार ने इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी कल्याण व विकास कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की है, जो सतत विकास लक्ष्यों के आदर्श वाक्य "कोई भी पीछे न छूटने पाए" के अनुरूप "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" के प्रति अपनी व्यापक वचनबद्धता से प्रेरित है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, जिला और स्थानीय सरकार के स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा एवं निरंतरता की प्राथमिक जिम्मेदारी रखते हैं। अपनी उपलब्धियों पर प्रभावी रूप से निगाह रखने के उद्देश्य से राज्यों को उनकी विशिष्ट विकासात्मक प्राथमिकताओं, डेटा आवश्यकताओं, बुनियादी ढांचे और संसाधन उपलब्धता के अनुसार अपने स्वयं के राज्य संकेतक ढांचे (एसआईएफ) विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी के रूप में नीति आयोग, जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्रगति की निगरानी हेतु जिला संकेतक फ्रेमवर्क (डीआईएफ) विकसित करने में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करता है। इसे मान्यता देते हुए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उप-राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य निगरानी ढांचे के निर्माण, समीक्षा और परिशोधन में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सक्रिय रूप से तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। इस प्रयास में वर्ष 2019 में, मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर की निगरानी रूपरेखा तैयार करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए और प्रसारित किए। दिशानिर्देश का बाद में मार्च 2022 में "उप-राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी पर निगरानी ढांचे पर मार्गदर्शन" शीर्षक वाली रिपोर्ट के हिस्से के रूप में अद्यतन किया गया।

यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

संसदीय प्रश्नः तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) दिशानिर्देश

(जीएनएस)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर विकास की अनुमति देते हुए तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा, इकोसिस्टम के संरक्षण और मछली पकड़ने तथा अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1991 से तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना लागू कर रहा है। 1991 की अधिसूचना को वर्ष 2011 में सीआरजेड/द्वीप संरक्षण क्षेत्र (आईपीजेड) अधिसूचना से बदल दिया गया था और बाद में वर्ष 2019 में सीआरजेड/द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (आईसीआरजेड) अधिसूचना द्वारा अद्यतन किया गया था। 2019 की अधिसूचना के अंतर्गत, सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं (सीआरजेडपीएस), द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र योजनाओं (आईसीआरजेडपीएस) या एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाओं (आईआईएमपीएस) को अपडेट करना होगा और उन्हें अनुमोदन के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत करना होगा, जब तक इन नई योजनाओं को अनुमोदित नहीं किया जाता है, सीआरजेड / आईपीजेड अधिसूचना, 2011 के प्रावधान लागू रहेंगे। अब तक, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल के लिए नए सीजेडएमपी और ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान के लिए आईसीआरजेडपी को मंजूरी दी गई है।

सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अंतर्गत सीजेडएमपी का नई सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अनुलग्नक- क्ष में निर्धारित दिशानिदेर्शों के अनुसार है, जो पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच किसी भी अंतर के बिना पूरे देश में लागू हैं। तटीय जोन प्रबंधन योजना (सीजेडएमपी) को अपडेट करने के लिए दिशा-निदेर्शों के अनुरूप अपेक्षित अध्ययन और सर्वेक्षण संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मंत्रालय के प्राधिकृत संस्थानों के माध्यम से किए जा रहे हैं।

सीआरजेड अधिसूचनाओं, 2011 और 2019 का उल्लंघन, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने देश में उल्लंघनों से निपटने और सीआरजेड विनियमों को लागू करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5, 10 और 19 के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरणों (सीजेडएमए) को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

आन्ध्र प्रदेश तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण (एपीसीजेडएमए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले दस वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में उल्लंघन के कुल 53 मामलों की सूचना मिली है जिनमें से किसी में भी बार-बार अपराध करने वाले शामिल नहीं हैं। बापतला जिले सहित जिले के अनुसार विवरण नीचे दिए गए हैं:

जीओआईस्टैट्स मोबाइल एप्लिकेशन की विशेषताएं और इस्तेमाल

(जीएनएस)।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों की प्रदान करने के उद्देश्य से 29 जून, 2025 को जीओआईस्टैट्स ऐप शुरू किया गया था। तदनुसार, चयनित सामाजिक-आर्थिक संकेतकों जैसे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण और असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण के आंकड़े इस ऐप पर उपलब्ध कराए जाते हैं। पोर्टल में वर्तमान में छह डोमेन हैं, जिनमें नौ संकेतक शामिल हैं।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जीओआईस्टैट्स ऐप के उपयोग के आंकड़े रखता है। 11 अगस्त, 2025 तक जीओआईस्टैट्स ऐप के 8040 डाउनलोड हैं। यह एप्लिकेशन डेटा पृथक्करण की सुविधाओं के माध्यम से सहायता करता है। वर्तमान में, ऐप में डेटा सीमित रूप से उपलब्ध है, क्योंकि ऐप का उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी आधारित डेटा प्रदान करना है। इसके अलावा, ई-सांख्यिकी पोर्टल पर उपलब्ध पृथक डेटा तक पहुंचने के लिए ऐप पर लिंक प्रदान किए गए हैं। चयनित संकेतक का समय श्रृंखला दृश्य ऐप पर दिया गया है।

यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने पवित्र श्रावण माह के अंतिम सोमवार को सोमनाथ महादेव का दर्शन-पूजन किया

श्रावण माह के हर सोमवार को पौराणिक शिव मंदिरों में श्रद्धापूर्वक दर्शन-पूजन के उपक्रम में सोमनाथ दादा के दर्शन को पहुँचे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री ने सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से आँगनबाड़ियों के नन्हें बच्चों के लिए दैनिक लड्डू पोषण प्रसाद वितरण का शुभारंभ कराया

सोमनाथ ट्रस्ट लगभग 1 करोड़ रुपए के खर्च से बच्चों को लड्डू प्रसाद के रूप में 28 टन पोषणयुक्त आहार देगा

आगामी एक वर्ष में 7 लाख लड्डू वितरण

हर लड्डू प्रसाद पैकिंग इकोफ्रेंड्ली मटीरियल से की जाती है

प्रधानमंत्री तथा सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 'पोषण भी, पढ़ाई भी' मंत्र को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने साकार किया

गांधीनगर, 18 अगस्त :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने पवित्र श्रावण माह के अंतिम सोमवार को भक्ति, भव्यता तथा दिव्यता के प्रतीक समान भगवान सोमनाथ महादेव का भावपूर्वक दर्शन-अर्चन तथा जलाभिषेक किया।

मुख्यमंत्री ने इस श्रावण माह के हर सोमवार को पौराणिक शिव मंदिरों में दर्शन-पूजन का उपक्रम श्रद्धापूर्वक प्रारंभ किया है। तद्अनुसार उन्होंने श्रावण के प्रथम सोमवार को गांधीनगर के निकट स्थित धोळेश्वर महादेव, दूसरे सोमवार को भरूच के कावी-कंबोई स्थित स्तंभेश्वर महादेव तथा तीसरे सोमवार को ऐतिहासिक धरोहर समान वडनगर स्थित हाटकेश्वर महादेव का दर्शन-पूजन किया था।

पवित्र श्रावण माह के अंतिम सोमवार को मुख्यमंत्री द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम तथा सौराष्ट्र के सुप्रसिद्ध सोमनाथ महादेव के दर्शन-पूजन के लिए पहुँचे और उन्होंने भगवान भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाकर दर्शन कर सबके मंगल एवं राज्य-राष्ट्र की प्रगति व सुख-समृद्धि की प्रार्थना की।

श्री पटेल ने इस अवसर पर सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से गीर सोमनाथ जिले की आँगनबाड़ियों के नन्हें बच्चों के लिए दैनिक लड्डू पोषण प्रसाद वितरण का शुभारंभ कराया।

प्रधानमंत्री तथा सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र मोदी ने 'पोषण भी, पढ़ाई भी' का मंत्र देकर बच्चों के अभ्यास के साथ पषण की भी चिंता की है।

ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री की प्रेरणा व मार्गदर्शन में इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए आगामी एक वर्ष में गीर सोमनाथ जिले में 7 लाख लड्डू प्रसाद वितरण का सेवायज्ञ शुरू किया है। ट्रस्ट लगभग 1 करोड़ रुपए के खर्च से 28 टन लड्डू का पोषणक्षम आहार आँगनबाड़ी बच्चों तक पहुँचाएगा।

मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ कराए गए इस दैनिक पोषण प्रसाद वितरण में दिए जाने वाले लड्डू की पैकिंग के लिए ट्रस्ट ने मानव हस्तक्षेप रहित ऑटोमैटिक पैकेजिंग मशीन विकसित की है, जिसके उपयोग से लड्डू को एयरटाइट व पूरी तरह स्वच्छता के साथ पैक किया जाता है।

इतना ही नहीं; पर्यावरण संरक्षण के प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप इस लड्डू की पैकिंग में बायोडिग्रेडेबल मटीरियल का उपयोग किया गया है। ट्रस्ट ने सोमनाथ दादा के पोषण प्रसाद का वितरण आगामी एक वर्ष तक अविरत करने का आयोजन भी किया है।

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ट्रस्ट सामाजिक सेवाकी परंपरा भी निभाता आया है। ट्रस्ट हर वर्ष आम के मौसम में सोमनाथ महादेव के समक्ष 'आम मनोरथ' आयोजित कर जिले की आँगनबाड़ी के बच्चों को लगभग 2500 किलो आम का वितरण करता है। कुछ समय पहले ही कच्छ के मीठे छुहारे (सूखे खजूर) केमनोरथ का आयोजन कर 1500 किलो छुहारे आँगनबाड़ियों में वितरित किए गए। विशेष रूप से जिले की आँगनबाड़ियों में ट्रस्ट ने दैनिक 50 ग्राम मूंगफली एवं गुड़ से बने गजक (चिक्की) का पोषण आहार के रूप में एक वर्ष तक वितरण किया गया।

ट्रस्ट 'सौना नाथ सोमनाथ (सबके नाथ सोमनाथ)' के ध्येय के साथ समाज के हर वर्ग को छूटने वाली सेवाएँ करता आया है। सोमनाथ महादेव को अर्पित पीतांबर तथा माता पार्वती को अर्पित साड़ियाँ पिछले दो वर्ष में 17 हजार से अधिक जरूरतमंदों को वस्त्र प्रसाद के रूप में पहुँचाए गए।

हर महीने दंत रोग निदान शिविर, कृत्रिम अंग वितरण, फिजियोथेरेपी सेवा, सर्वरोग निदान शिविर की सेवा का हजारों लोगों को लाभ मिलता है। ट्रस्ट की गीर गौशाला में उत्तम गौवंश का संवर्धन तथा राज्य की गौशालाओं में नंदी प्रसाद देकर गुजरात की गुजरात की गौशालाओं में गीर गायों के वंश सुदृढ़ीकरण का कार्य भी ट्रस्ट करता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में अखंड सेवा की अलख जगाने वाला श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट भक्तों के लिए स्वच्छता, पवित्रता, स्वास्थ्य एवं समानता का पर्याय है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सोमनाथ ट्रस्ट की बहुमुखी सेवा गतिविधियों की भी जानकारी प्राप्त की। ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री जे. डी. परमार तथा सचिव श्री योगेन्द्र देसाई ने मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री के सोमनाथ दर्शन अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजुलाबेन मूछार, विधायक सर्वश्री प्रद्युमनभाई वाजा, भगवानभाई बारड, काळूभाई राठौड़, वेरावळ-पाटण संयुक्त नगर पालिका की अध्यक्ष श्री पल्लवीबेन जानी, जिला कलेक्टर श्री एन. वी. उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी श्री स्नेहल भापकर, जिला पुलिस अधीक्षक श्री मनोहरसिंह जाडेजा, अग्रणी सर्वश्री झवेरीभाई ठकरार, संजय परमार, पूर्व विधायक सर्वश्री जशाभाई बारड, राजशीभाई जोटवा, अग्रणी सर्वश्री महेन्द्रभाई पीठिया, मानसिंह परमार सहित पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

पर्यटन से जुड़ी अवसंरचना का विस्तार

(जीएनएस)।

जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन से जुड़ी अवसंरचना का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र-शासित प्रदेश के प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, स्थानीय एवं देशी भाषाओं में पर्यटन सामग्री और संकेतक भी संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र-शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा विकसित किए जाते हैं।

हालांकि, पर्यटन मंत्रालय अपनी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी2.0)', 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' -स्वदेश दर्शन की एक उप-योजना और 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' योजनाओं के जरिए राज्य सरकारों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके पर्यटन से जुड़ी अवसंरचना के विकास के प्रयासों को पूरा करता है। यह सहायता धन की उपलब्धता, योजना के दिशानिदेर्शों के पालन, राज्य सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पेश करने आदि के अधीन है। इसके अलावा, भारत सरकार ने अपनी 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई)' पहल के तहत भी पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं के विकास हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इन योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में हरित आवागमन, संकेतक आदि से संबंधित परियोजनाओं सहित कई घटक शामिल हैं ताकि आगंतुकों और पर्यटकों को पर्यटन से जुड़ी बेहतर सुविधाएं एवं अनुभव प्रदान किए जा सकें।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से, पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 'जनजातीय गृह-स्थलों के विकास' की पहल की है। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन से जुड़ी संभावनाओं का दोहन करना और जनजातीय समुदाय को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। इस पहल में जनजातीय घरों व गांवों को निम्नलिखित बातों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है:

(a) ग्राम समुदाय की आवश्यकता के लिए 5 लाख रुपये तक

(b) प्रत्येक घर के लिए दो नए कमरों के निर्माण हेतु 5 लाख रुपये तक

(c) प्रत्येक घर के लिए मौजूदा कमरों के नवीनीकरण हेतु 3 लाख रुपये तक

तदनुसार, पर्यटन मंत्रालय ने जनजातीय क्षेत्रों में गृह-स्थलों (होमस्टे) के विकास हेतु योजनाबद्ध दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये योजनाबद्ध दिशानिर्देश विशेष रूप से पंचायतों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार (पेसा) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख नहीं करते हैं। हालांकि, उक्त योजनाबद्ध दिशा-निदेर्शों के अनुसार, राज्य सरकारों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के प्रशासन को गृह-स्थलों (होमस्टे) के निर्माण/नवीनीकरण हेतु जनजातीय क्षेत्रों में उपयुक्त जनजातीय गांवों व जनजातीय लाभार्थियों की पहचान करनी होगी और यह कार्य स्थानीय समुदाय के परामर्श से किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य/केन्द्र-शासित प्रदेश इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय को परियोजना प्रस्तुत करेंगे और संबंधित राज्य/ केन्द्र-शासित प्रदेश की कार्यान्वयन एजेंसी को धनराशि जारी की जाएगी, जो आगे चलकर व्यक्तिगत लाभार्थियों/ग्राम समुदायों को एक सुपरिभाषित और पारदर्शी तरीके से धनराशि वितरित करने के लिए जिम्मेदार होगी। योजनाबद्ध दिशानिर्देश संबंधित राज्यों को मौजूदा कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन के अनुरूप योजना के कार्यान्वयन हेतु संचालन संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने का भी सुझाव देते हैं।

यह जानकारी केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

सलमान खान की वो हीरोइन जिसने किया 20 मर्डर के आरोपी 'गैंगस्टर' के साथ काम, बताई शूटिंग के वक्त कैसी थी हालात

(जीएनएस)।

सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया से भाग्यश्री ने डेब्यू किया था। ये फिल्म दोनों के करियर के की बड़ी हिट फिल्म बन गई थी। इस फिल्म ने भाग्यश्री को बड़ी पहचान दिलवाई। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर का बेस्ड डेब्यू अवॉर्ड भी मिला। लेकिन एक बार भाग्यश्री को एक फिल्म में गैंगस्टर के साथ काम करना पड़ा था।

जिस गैंगस्टर के साथ उन्होंने काम किया वो छोटा मोटा नहीं था। बल्कि उसके ऊपर 20-30 लोगों के मर्डर का आरोप था। जब भाग्यश्री की गैंगस्टर से पहली मुलाकात हुई, तो वो घबरा गईं थी। वैसे ये बात सालों पहले की है।

दूरदर्शन स'ह्री को दिए एक इंटरव्यू में भाग्यश्री ने इस को विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा, एक तेलुगु फिल्म थी, जिसे जेल में बंद अपराधियों के साथ बनाना था। मौजूदा सरकार ने इसकी अनुमति दी थी। तब अपराधियों को जेल से बाहर शूटिंग के लिए लाया गया था। फिल्म की कहानी इन अपराधियों के निजी जीवन से प्रेरित थी। फिल्म की शुरूआत में मैं गैंगस्टर के साथ काम करने को लेकर बहुत डरी हुई थीं।

लेकिन जब वह सेट पर उनसे मिलीं, तो उनका डर धीरे-धीरे कम हो गया। फिल्म में मेरा रोल एक पत्रकार का था। उस फिल्म का कॉनसेप्ट भी बेहद शानदार था। शूटिंग के दौरान ही मुझे पता चला था कि उस गैंगस्टर ने 20-30 लोगों का मर्डर किया हुआ है।

आगे भाग्यश्री ने बताया, पहली नजर में मैं गैंगस्टर का लुक देख हैरान हो गई थी। उसने केसरिया कपड़े पहने थे। गले में भी कई सारी चेन पहनीं थी। इतना ही नहीं उसके साथ बॉडीगार्ड भी थे। वो जब मेरे पास आया तो उसने तुरंत कहा मुझे तुम बहुत पसंद हो। इसके बाद मेरी सांसे अटक गई थी। हालांकि मुझे राहत की सांस तब आई, जब उसने कहा मैं उसकी बहन की तरह दिखती हूं।

बता दें, हिट फिल्म देने के बाद भाग्यश्री अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गई थीं। साल 1989 में उन्होंने हिमालय दासानी से शादी की थी। इसके बाद भी वो फिल्मों से दूर हैं। उनके बेटे अभिन्यु दसानी ने भी फिल्म इंडस्ट्री जॉइन की है। बतौर एक्टर उनकी कई फिल्में आई हैं।

हिजाब के लिए पत्नी को ट्रोल करने वालों को इरफान पठान का जवाब, कैसे करते हैं लोगों को डील?

(जीएनएस)।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने हाल ही में लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात की है। इसमें उन्होंने अपने जमाने के गेम, ड्रेसिंग रूम के किस्सों से लेकर आईपीएल में कमेंट्री पैनल से बाहर करने तक पर अपनी बात रखी है। इस बीच ट्रोल्स को लेकर भी उनकी प्रतिक्रिया आई है।

जब उनसे सवाल किया गया कि आपकी पत्नी की फोटो चेहरे पर हाथ रखकर पोस्ट की गई थी, तो लोगों ने ट्रोल किया था, आपको कैसा लगता है और इस तरह के ट्रोल्स से आप कैसे डील करते हैं। पठान ने कहा कि लोग हिजाब को लेकर भी ट्रोलिंग करते हैं।

पठान ने कहा कि मेरे घर में मेरी मां लीडर हैं, मेरे पिता भले ही घर से बाहर लीडर हैं। उसी तरह मेरी पत्नी भी मेरे घर में लीडर हैं। शुरूआत में मुझे बुरा लगता था कि कोई उनको ट्रोल करता है। जब आपनी पत्नी के बारे में कोई कुछ बोलता है, तो यह सही तो नहीं लगता है।

पठान ने कहा कि मेरी पत्नी को भी

बुरा लगता था और मैं यही कहा करता था कि आप कमेंट्स मत पढो। ट्रोलिंग जो भी हुई है, वह गलत तरीके से हुई है और यह बिलकुल सही नहीं है। इसके बाद पठान उस कहानी पर चले गए कि कैसे उन्होंने अपनी पत्नी सफा बैग से मुलाकात की थी।

पठान ने कहा कि उनकी मुलाकात सफा से सोशल मीडिया से हुई थी, उन्होंने यह नहीं बताया कि सोशल मीडिया में किस प्लेटफॉर्म पर दोनों की बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने कभी डेटिंग नहीं की, जब मिले तब सगाई कर ली और छह महीने में शादी भी कर ली। 10 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी।

पठान ने कहा कि सोशल मीडिया पर पहला मैसेज उन्होंने ही सफा बैग को किया था और ऐसा क्यों किया था, उसके पीछे भी एक कहानी है। वह कहानी पत्नी साथ में होंगी, तभी बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी एक मजबूत महिला हैं और दस साल बाद दोनों का जीवन खुशी से चल रहा है।

गौरतलब है कि इरफान पठान ने कुछ मौकों पर अपनी पत्नी के साथ फोटो पोस्ट किये हैं, तो ट्रोल्स ने उनको हिजाब नहीं पहनने की सलाह दी और काफी कुछ सुनाया है। चेहरा नहीं दिखाया था, तब भी ट्रोलिंग होती रही है और चेहरा दिखाने पर भी ट्रोलिंग चलती रही हैं।

कांग्रेस का हल्ला बोल, जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, जयवर्धन की नियुक्ति पर भी दी सफाई

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश कांग्रेस में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आज, 18 अगस्त 2025 को भोपाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए, इसे "भाजपा का एजेंट" और "लोकतंत्र का चोर" करार दिया। इसके साथ ही, उन्होंने राघौगढ़ में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर उठे विवाद पर भी सफाई दी, जिसमें जयवर्धन सिंह का नाम चर्चा में रहा।

मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जयवर्धन सिंह भी मौजूद थे। पटवारी ने वोट चोरी के मुद्दे पर 25 अगस्त से 5 सितंबर तक पूरे प्रदेश में आंदोलन की घोषणा की, जिससे मध्य प्रदेश की सियासत में नया तूफान खड़ा होने की आशंका है।

चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप

जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का प्रहरी नहीं, बल्कि इखढ का एजेंट बन गया है। यह चोर की तरह काम कर रहा है।" पटवारी ने दो इखढ नेताओं-सांसद जनार्दन मिश्रा और मंत्री अनुराग ठाकुर-के बयानों का हवाला देते हुए दावा किया कि ये नेता स्वयं वोट चोरी और चुनावी गड़बड़ियों की बात स्वीकार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "जनार्दन मिश्रा ने खुलेआम कहा कि उन्होंने हर घर जाकर 1000-1000 फर्जी वोट सत्यापित किए। मैंने इसका वीडियो अपने अकाउंट पर शेयर किया है। इसी तरह, अनुराग ठाकुर ने रायबरेली में वोट बढ़ने की बात कही। ये दोनों बयान साबित करते हैं कि इखढ चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी कर रही है, और चुनाव आयोग इस पर चुप है।"

पटवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे का समर्थन करते हुए कहा, "राहुल जी ने जो सवाल उठाया, अब इखढ नेता भी वही बातें कह रहे हैं। लेकिन आयोग उनकी दलीलों को दोहरा रहा है। यह लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का सवाल है।" उन्होंने सवाल उठाया कि जब इखढ नेता खुले तौर पर गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं, तो आयोग कांग्रेस नेताओं से हलफनामा क्यों मांग रहा है। "आयोग को खुद जनता के सामने हलफनामा देना चाहिए कि इस बार वोट चोरी नहीं होगी," पटवारी ने तंज कसते हुए कहा।

आंदोलन की घोषणा

पटवारी ने ऐलान किया कि वोट चोरी और चुनाव आयोग की कथित पक्षपातपूर्ण भूमिका के खिलाफ कांग्रेस 25 अगस्त से 5 सितंबर 2025 तक मध्य प्रदेश में व्यापक आंदोलन करेगी। इस दौरान सभी जिलों में प्रदर्शन, रैलियाँ, और सभाएँ आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कार्यकताओं से अपील की कि वे इस मुद्दे को जन-जन तक ले जाएँ और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हों।

पटवारी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को डराने-धमकाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस इस दबाव में नहीं झुकेगी। "हमारी लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है। हम हर उस संस्था को जवाब देंगे जो इखढ के इशारे पर काम कर रही है," उन्होंने कहा।

जिला अध्यक्ष नियुक्ति पर विवाद और सफाई

हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर विवाद सुर्खियों में रहा, खासकर राघौगढ़ में जयवर्धन सिंह की भूमिका को लेकर। जीतू पटवारी ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा, "जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में मेरा कोई व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं है। ये नियुक्तियाँ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप की गई हैं। राहुल जी ने खुद कई नेताओं से इस सिलसिले में चर्चा की थी, जिनमें जयवर्धन सिंह भी शामिल थे।"

पटवारी ने अपनी नाराजगी को स्पष्ट करते हुए कहा, "मुझे जयवर्धन से थोड़ा गुस्सा था, क्योंकि राघौगढ़ में उनकी सिफारिश पर नियुक्ति की बात

पाकिस्तान : बाढ़ से मर गए 657 लोग, लेकिन शरीफ चीनी विदेश मंत्री के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त

(जीएनएस)।

पाकिस्तान इस समय मॉनसून की भयंकर तबाही झेल रहा है, जहां 26 जून से अब तक बारिश संबंधी घटनाओं में 650 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। स्थानीय समाचार पत्र 'डॉन' के अनुसार, यह हाल के वर्षों के सबसे घातक मॉनसून में से एक है। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान में हाल ही में आई बाढ़ से हुए जान-माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

UN हुआ एक्टिव लेकिन पाक सरकार सुस्त

गुटेरेस ने रविवार को अपने प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक द्वारा जारी एक बयान में पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सभी प्रभावितों के साथ एकजुटता का इजहार किया। पीटीआई के अनुसार, बयान में कहा गया है, "संयुक्त राष्ट्र की टीमें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सरकारों के संपर्क में हैं।"

चीनी विदेश मंत्री स्वागत में व्यस्त शरीफ मियां

वहीं प्रधानमंत्री इस त्रासदी का दौरा करने के बजाय 20 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के होने वाले

दौरे में व्यस्त हैं। उन्होंने अभी तक किसी भी तरह मुआवजे का ऐलान न तो मृतकों के परिजनों के लिए किया, न घायलों के लिए और न ही जिन्हें इस बाढ़ में भयंकर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।

देशभर में 650 से ज्यादा मौतें

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के आंकड़ों के मुताबिक, जून के अंत से लेकर अब तक पाकिस्तान में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 657 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 171 बच्चे और 94 महिलाएँ शामिल हैं।

खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा प्रभावित

खैबर पख्तूनख्वा में 323 लोगों की मौत और 150 के लापता होने की खबर है, जिससे यह प्रांत आपदा का केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री के आदेश पर संघीय मंत्री यहाँ राहत कार्यों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।

गिलगित-बाल्टिस्तान में खाने की किल्लत

गिलगित-बाल्टिस्तान में अचानक आई बाढ़ ने कई गाँवों को अलग-थलग कर दिया है, कृषि भूमि को नुकसान पहुँचाया है और मुख्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे समुदायों को बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित होना पड़ा है। लंबी अवधि की कमी को लेकर गिलगित शहर में निवासियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया।

एनडीएमए की सितंबर में और बारिश की चेतावनी

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगले महीने दो से तीन और भारी बारिश के दौर आने की आशंका है, जिससे आगे और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

संयुक्त राष्ट्र सहायता के लिए तैयार

महासचिव गुटेरेस ने दोहराया कि भारत और पाकिस्तान दोनों में संयुक्त राष्ट्र की देश टीमें सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं और वे आपदा पीड़ितों के साथ एकजुटता से खड़ी हैं।

प्रधानमंत्री का राहत निर्देश

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कैबिनेट सदस्यों को केपी जिलों में सीधे सहायता वितरण की निगरानी करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत संघीय मंत्रियों को शांगला, बुनेर, मनसेहरा और बाजौर में तैनात किया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला क्षेत्र में दो पुलिस अधिकारियों द्वारा एक पत्रकार पर कथित हमले का स्वतः संज्ञान लिया गया

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के बटाला इलाके में दो पंजाब पुलिस अधिकारियों द्वारा एक पत्रकार पर सरेआम हमला करने की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, घटना के एक वीडियो में, पीड़ित बेसुध पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पुलिसकर्मी उस पर हमला करने के बाद भाग रहे हैं।

आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट की सामग्री सत्य है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। इसलिए, आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जाँच की स्थिति और पीड़ित पत्रकार के स्वास्थ्य की जानकारी शामिल होने की उम्मीद है।

7 अगस्त, 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 1 अगस्त, 2025 को हुई थी। दोनों पुलिस अधिकारी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कानून- व्यवस्था बनाए रखने के लिए बटाला में तैनात थे। पत्रकार ने कथित तौर पर उनकी उपस्थिति के बारे में कुछ सवाल पूछे जिससे वे भड़क गए और उन्होंने पत्रकार पर हमला कर दिया।*